मुख्य पृष्ठ
उ.प्र. विशेष
राष्ट्रीय
प्रमुख खबरें
वाणिज्य
संपादकीय
दृष्टिकोण
अंतरराष्ट्रीय
खेल
फीचर
फोटो गैलरी
वर्गीकृत

संपादकीय

छापों से नहीं मिटेगा भ्रष्टाचार

जम्मू-क
गुज
और....
राज
अपन

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पिछले दो दिनों में सरकारी अधिकारियों के यहां जो छापे डाले और इस दौरान इन अधिकारियों के पास से जिस तरह आय से अधिक सम्पत्ति मिली उससे एक बार पुन: इस बात की पुष्टि हुई कि सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जा रहा है। इस वर्ष यह चौथा अवसर है जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने देश भर में भ्रष्ट अधिकारियों के यहां छापे डालकर रिश्वतखोरी और गबन के मामले उजागर किए। इस बार जिन सरकारी अधिकारियों के यहां छापे डाले गए वे अधिकारी रेलवे, बैंक, आयुध कारखानों, पेट्रोलियम कम्पनियों, सीमा शुल्क आदि विभागों से सम्बन्धित हैं। इससे यही पता चलता है कि भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है और वह जमकर फल-फूल भी रहा है। यदि यह सोचा जा रहा है कि अपने पदों का दुरुपयोग कर दोनों हाथों से धन बटोरने वाले चंद भ्रष्ट अधिकारियों के यहां छापे डालकर भ्रष्टाचार की विकराल होती समस्या पर काबू पाया जा सकता है तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। भ्रष्ट सरकारी अधिकारी इस प्रकार के छापों से भय खाने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे अपने बचने की कोई न कोई राह निकाल ही लेते हैं। दरअसल भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों ने अपने बचाव का एक तंत्र भी विकसित कर लिया है। यह कोई छिपी बात नहीं कि घपले-घोटाले और रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़े गए ज्यादातर भ्रष्ट अधिकारी अंतत: बच ही निकलते हैं। इस संदर्भ में पूर्व सतर्कता आयुक्त एन. विट्ठल की इस टिप्पणी को विस्मृत नहीं किया जा सकता कि 'भारत में भ्रष्टाचार सबसे कम जोखिम और सबसे अधिक लाभ वाला धंधा बन चुका है।' भ्रष्ट अधिकारियों की संख्या इसीलिए बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें आसानी से दण्डित नहीं किया जा सकता।

भ्रष्टाचार पर तो तभी अंकुश लग सकता है जब भ्रष्ट कार्यों में लिप्त व्यक्तियों को दण्ड पाने का भय हो। हमारे देश में तो स्थिति यह है कि जो भ्रष्ट व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर है उसके दण्डित होने की संभावना उतनी ही कम है। वस्तुत: इस स्थिति के कारण ही भ्रष्टाचार दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ता चला जा रहा है। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति दिन-प्रतिदिन दुस्साहसी और निर्द्वन्द्व होते चले जा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसे कोई उपाय क्यों नहीं किए जा रहे हैं जिससे भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों में भय का संचार हो? भ्रष्टाचार पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के उपायों को अमल में लाने के मामले में जिस तरह अनिच्छा का परिचय दिया जा रहा है उससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे लोग जानबूझकर भ्रष्टाचार की उपेक्षा करने में लगे हुए हैं। देश के प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की जैसी उपेक्षा की जा रही है उससे आम जनता के मन में यह धारणा तेजी के साथ घर करती चली जा रही है कि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के चलते ही भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ कोई कठोर कदम जानबूझकर नहीं उठाए जा रहे हैं। देश के राजनीतिक दल चाहे जैसा दावा क्यों न करें, अब यह स्पष्ट है कि वे भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर बहानेबाजी ही अधिक कर रहे हैं। यह बहानेबाजी अब और अधिक समय तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि आम जनता यह अच्छी तरह समझ रही है कि इस देश की राजनीति कालेधन पर आश्रित है और यह कालाधन प्रशासनिक भ्रष्टाचार के बलबूते ही जुटाया जा रहा है। भले ही हर राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में यह दर्ज रहता हो कि भ्रष्टाचार से कठोरता से निपटा जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सच तो यह है कि भ्रष्टाचार से निपटने के मामले में कठोरता के स्थान पर नरमी का ही परिचय अधिक दिया गया है।

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस उपाय अमल में न लाना एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है। विडम्बना यह है कि इस भ्रष्टाचार का परिचय सभी राजनीतिक दल दे रहे हैं। वर्तमान में कोई भी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि न तो लोकपाल विधेयक कानून का रूप ले पा रहा है और न ही आम जनता को सूचना का अधिकार प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। इसी तरह सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए भी कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। यही नहीं प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सतर्कता आयोग द्वारा सुझाए गए अधिकांश उपायों को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उपायों के संदर्भ में जिस तरह खोखले आश्वासनों की घुट्टी पिलाई जा रही है उससे यही अधिक स्पष्ट होता है कि हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है। नि:संदेह यह समझौता समाज और राष्ट्र के साथ किया जाने वाला एक बहुत बड़ा धोखा ही है। यदि भ्रष्टाचार इसी गति से बढ़ता रहा तो यह लगभग तय है कि आम आदमी के मन में लोकतंत्र और उसकी व्यवस्थाओं के प्रति जो आस्था है वह अधिक समय तक अक्षुण्ण नहीं रह सकेगी। अच्छा यह

होगा कि देश का राजनीतिक नेतृत्व यह समझ ले कि भ्रष्टाचार की रोकथाम न करके वह भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का ही कार्य कर रहा है और साथ ही देश को पतन की एक ऐसी खाई में ले जा रहा है जहां से निकलना यदि असंभव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है।

हमें जानिए ई-ग्रीटिंग्स हमसे संपर्क करें हमसे पूछिए

जागरण रिसर्च सेंटर संपादक के नाम पत्र विज्ञापन पिछले अंक